(b) if so, whether Personnel Department Office Memorandum No. 28034/7/ 86 Estt. (A) dated 3rd April, 1986 with instructions of Fifth Pay Commission, regarding posting of husband and wife at the same station, have at all been implemented in technical staff, despite having vacancies, especially, when their children are under ten years old;

(c) if so, the details of such persons whose requests were received; and

(d) the action taken with reasons of delay?

THE MINISTER OF INFORMA TION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Instructions of Depart ment of Personnel & Training are im plemented within the constraints of ad ministrative feasibility.

(c) and (d) Only one request was received. The officer had an uninterrupted stay since 1981 and was transferred in 1997 to Balasore and then to Calcutta on his own request.

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले व्यापारिक घराने

3035. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और त्रिपुरा में 31 मार्च, 1997 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले व्यापारिक घरानों की संख्या क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1996 और 1996 को लाभ दिखा रहे थे; और

(ग) एम. आर. टी. पी. के अन्तर्गत आने वेल उन गैर-बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय घरानों का ब्यौरा क्या है जो 31 मार्च, 1995 और 1996 को लाभ दिखा रहे थे, और

(घ) उक्त एककों द्वारा 31 मार्च, 1996 तक आय कर, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. धम्बी दुरई): (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग क को 27.9.1991 से हटाए जाने के परिणाम स्वरूप, बड़े औद्योगिक घरानों को अब एम. आर. टी. पी. आधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः औद्योगिक घरानों से संबंधित आंकड़े कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अलग से नहीं एकत्र किये जाते हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय तथा गैर-बहुराष्ट्रीय कम्पनी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तथा सरकार बहुराष्ट्रीय के आधार पर देश में कार्यरत कम्पनियों के कोई आंकड़े नहीं रखती है।

Review of old and outdated laws

3036. SHRI GOVINDRAO ADIK: will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have ordered indepth review of old and outdated Laws and Regulations with a view to do away with redundant clauses and bring out desirable changes in the gamut of Indian Legislation to bring it on compatible level with the legal systems and framework in other advanced countries of the world;

(b) if so, the details of Government's thinking and plans afoot in this regard and details of the progress achieved so far; and

(c) the details of fresh initiatives proposed in this regard for further update?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Law commission of India has been requested to undertake study on review/repeal of obsolete laws and submit its Report thereon. The Government has also constituted a Commission for the review of administrative laws, regulations and procedures. Both the Law Commission of India and the commission of Review of Administrative Laws are presently examining the matter.